







## अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। आजादी के 74 वर्षों बाद प्रतापगढ़ को राजकीय मेडिकल कालेज की सौगत आज मिल गई। शहर से चार तिमी दूर रुपे के शवायराय में 213 करोड़ की लागत से निर्मित डा० सोनेलाल पटेल स्वचासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिद्धार्थ नगर से जैसे ही तर्ह उर्जली किया, पूरा मेडिकल कालेज तालियों की गणगाइट से गंग उठा। इस दौरान अतिथियों ने दौप प्रज्ञवलन किया।

इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी प्रदेश सभाकारे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खनन, वरेल मंत्री मोती सिंह के अलावा सांसद विनोद सोनकर व संगम लाल, कमिशनर संजय गोयल, डीएम, एसपी के अलावा विधायकान्द के नेताओं तथा मेडिकल कालेज के प्राचार्य व उनका पूरा स्टाफ मौजूद था। सिद्धार्थ नगर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज प्रदेश के 9



मेडिकल कालेजों के साथ प्रतापगढ़ का डा० सोनेलाल पटेल स्वचासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया जा रहा है। इसके बाद विधायकान्द के प्राचार्य व उनका पूरा स्टाफ मौजूद था। सिद्धार्थ नगर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डाक्टरों का लाग भगवान मनने

है। इनके साथ चिकित्सक भी जैसे छोटे जनपद में राजकीय अधिक से अधिक लोग बैहतर शिक्षा का लाभ उठा पाएं। मंत्री मोती सिंह ने आज के दिन को ऐतिहासिक क्षण बताया। सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले किसी

ने सोचा थी नहीं होगा कि प्रतापगढ़ जैसे छोटे जनपद में राजकीय मेडिकल कालेज खुलेगा। सांसद संगम लाल गुप्ता ने उन किसानों के धन्यवाद दिया जिन्होंने इस राजकीय मेडिकल कालेज के लिये मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताया।

## मालगाड़ी से कटकर वृद्ध की मौत

परियांत्र, प्रतापगढ़। प्रयागराज-लखनऊ रेलवे ट्रैक के परियांत्र रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर सोमपार की दोपहर लाखगंगा 11 बजे एनटीपीसी ऊचाहार से कोयला उतारकर बानराज को जा रही मालगाड़ी से विश्रुत गंगा के समने खम्बा के पास एक वृद्ध की देने के लिए दर्दनाक मौत हो गयी, जिसकी सूचना मालगाड़ी के चालक ने मानिकपुर स्टेशन मास्टर को दिया। जिसकी सूचना स्टेशन मास्टर ने परियांत्र रेलवे स्टेशन मास्टर विश्वाल को जानकारी दी। घटना के जानकारी मिलने ही ऊचाहार की रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को कार्य क्षेत्र के बाहर होने के कारण स्थानीय नवाबगंज पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने ही थाना प्रभारी रुकुमाराणा सिंह ने एस आई रामअद्यार यादव को भैंजा, युवा कल्याण एवं पंचायती राज राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार उपर्युक्त विवारी ने बताए मुख्य अधिकारी (विवारी) एवं उपर्युक्त विवारी ने बताए मुख्य अधिकारी (विवारी) एवं उपर्युक्त विवारी ने उनके त्याग एवं बलिदान का समर्पण नहीं करते हुए उनके परिजनों का अभिनन्दन किया। इस दौरान मंत्री उपर्युक्त विवारी ने अपने आस-पास के परिजनों को स्वच्छ रखने एवं भारत को प्राप्तिक मूल्य विवारों का संकलन दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को



# सम्पादकीय

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हो रही गंभीर,  
नहीं निकला हल तो जानें कैसे बढ़ता जाएगा खतरा

अमेरिका की अपनी तरह की पहली नैशनल इंटेलिजेंस इस्टीमेट रिपोर्ट में भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत उन 11 देशों में शामिल किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से चिंताजनक श्रेणी में माने गए हैं। अमेरिका की अपनी तरह की पहली नैशनल इंटेलिजेंस इस्टीमेट रिपोर्ट में भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत उन 11 देशों में शामिल किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से चिंताजनक श्रेणी में माने गए हैं। इरिपोर्ट के मुताबिक, ये ऐसे देश हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण सामने आने वाली पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिहाज से खासे कमज़ोर हैं। संयोग कहिए कि यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब उत्तराखण्ड में लगातार बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन के रूप में आई त्रासदी ने परे देश को सकते में डाल रखा है। जाहिर है, हमें इन चुनौतियों के मद्देनजर अपनी तैयारियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वैश्विक संदर्भ में देखें तो रिपोर्ट की टाइमिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इसी महीने के आखिर में ग्रासगो में कॉप 26 क्लाइमेट चैंज कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में ग्लोबल टेंपरेचर की दशा तय करने में चीन और भारत की अहम भूमिका रहने वाली है। आखिर चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। भारत भले चौथे नंबर पर है, लेकिन चीन के साथ जुड़ इसलिए जाता है क्योंकि इन दोनों ही देशों में उत्सर्जन की मात्रा साल-दर-साल बढ़ रही है। दूसरे और तीसरे स्थान पर मौजूद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन (इच्यू) अपना उत्सर्जन कम करते जा रहे हैं। हालांकि यह भी कोई छुपा तथ्य नहीं है कि भारत जैसे देशों के लिए उत्सर्जन कम करना आसान नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा कारक कोयले का बहुतायत में इस्तेमाल है, जिसे रातोरात कम करना संभव नहीं। एक तो इसके सारे विकल्प अपेक्षाकृत महंगे पड़ते हैं और दूसरी बात यह कि आज भी यह सेक्टर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। ऐसे में कोई भी बदलाव धीरे-धीरे ही किया जा सकता है। इसके अलावा इन बदलावों के आर्थिक पहलू की भी अनदेखी नहीं की जा सकती।

रिपोर्ट में ठीक अनुमान लगाया गया है कि इन बदलावों का खर्च उठाने के सवाल पर विकासशील और विकसित देशों के बीच कूटनीतिक रस्साकशी जारी रहने वाली है। खासकर इसलिए भी कि विकसित देश पेरिस समझौते के अनुरूप 2020 से सालाना 100 अरब डॉलर जुटाने में नाकाम रहे हैं, जिससे विकासशील देशों के लिए एनडीसी (नैशनल डिटरमिन्ड कन्ट्रीब्यूशन) गोल यानी उत्सर्जन कम करने से जुड़ी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पूरी करना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल, विभिन्न देशों की जिम्मेदारियां तय करते हुए भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि पर्यावरण संबंधी चुनौतियां अब इस कदर गंभीर रूप ले चुकी हैं कि इन्हें पूरी तरह राष्ट्रीय नजरिये से देखना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। इसके प्रभाव विश्वव्यापी हैं और दोष चाहे किसी भी देश के सिर पर ढाला जाए इसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसलिए रस्साकशी में उलझने के बजाय सबका जोर आम राय से रास्ता निकालने पर ही होना चाहिए। गणित की वह शाखा कौन सी है जो त्रिभुजों के कोणों से जुड़े संबंधों का अध्ययन करती है

इतनी मुश्किले क्यों हैं शादी और तलाक में जाने कैसे कोरोना महामारी की मजबूरियों ने दिखाई अदालतों को राह

रेणुका बिष्ट

इस साल दलिली और केरल हाईकोर्ट ने मैरिज रजिस्ट्रेशन चाहते वालों को विडियो कॉम्प्लेसिंग के जरिए हाजिरी की अनुमति दी है। दूसरे ओर बांद्रा की फैमिली कोर्ट ने दुर्बह में फंसी पतनी और बाली में रहने वाली पति को उनकी आपसी सहमति से तलाक लेने की इजाजत दे दी। सशरीर मौजूदगी पर जोर देने के बजाय इन बैंचों ने कपल्स के लिए अपनी अलग-अलग मर्जी पूरी करने का रास्ता आसान कर दिया। इन तरह देखा जाए तो भले ही महामारी ने शादी पर प्रशासनिक ठप्पे लगवाने वाली या तलाक के लिए अदालत के चक्कर काट रहे लोगों का मुश्किलें बढ़ाई हैं, पर इन्हीं मुश्किलों की बदौलत ऐसे उपायों को बढ़ाव मिला है जो पूरी तरह लागू हो जाएं तो भारत में शादी और तलाक लेने की प्रक्रिया में आसानी से सुधार हो सकता है।

**तारीख पर तारीख :** तेलाक चाहने वाले जोड़ों के रास्ते से हटना जाहिर तौर पर अदालतों के भी हित में है। निचली अदालतों में लंबियां मुकदमों की संख्या पहली बार 4 करोड़ को पार कर गई है। यहां तक तिथि परिवर्तिक अदालतें भी, जो कि 1984 में कानून बनने के बाद अस्तित्व में आई थीं और जिनका मकसद वैवाहिक मामलों के आसान और सस्ते समाधान को संभव बनाना था, अब 'तारीख पर तारीख' के उसी जाल में फंस गई है, जिसका वे हल निकालने वाली थीं।

कोरोना का साया, सुप्रीम कोर्ट में विडियो कॉर्नफ्लिंग के जरिए सुनवाई  
सिस्टम से जुड़े जिन विलंबों के सूत्र वयस्क नागरिकों को बच्चे मानने वाली मानसिकता में मिलते हैं, उनका समाधान नागरिकों की पसंद का सम्मान सुनिश्चित करने वाली सोच में तलाशा जा सकता है। जज

का सम्मान युनाइटेड करने वाला साथ में तलाशा जा सकता है। जु़नून को 'विवाह संस्था की रक्षा करने और संरक्षित रखने' की जिम्मेदारी देनी चाही

# महिलाओं को 40 प्रतिशत

विषयाली नामों का उपयोग ये ५० से अधिक बारहज़ानों का देखा जाया जाता है। इनमें से एक देश की राजनीति में खलबली मच गई। जहां एक तरफ समतावादी राजनीति के समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया वर्हीं दूसरी तरफ विपक्ष की कुछ आवाज़ों ने इस फैसले को झुस्टंटक़् भास्त्र ठहरा दिया। उनका तरक़ि है की कांग्रेस ने केवल एक ही राज्य में यह घोषणा की तो इस फैसले के विरोधी राजनीति में प्रतीकात्मकता की अहमियत को कम कर दिया जाएगा। यदि कांग्रेस अन्य राज्यों में यह प्रयोग ना भी कर पाए तो उनमें भी इस फैसले का महत्व कम नहीं होता। सामाजिक बदलाव रातेरात होने वाली चीज़ नहीं है बल्कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इस फैसले को एक सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। इस फैसले ने महिलाओं के सवाल को भारत की पुरुषप्रधानी की राजनीति में कुछ देर के लिए ही सही लेकिन केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। वर्तमान राजनीतिक विमर्श में महिलाओं के मुद्दे मात्र उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सीमित रह गए हैं। महिलाओं का मुद्दा कानून व्यवस्था दुर्स्त करने का मुद्दा बनकर रह गया है। आलम यह है कि दक्षिणांशी ताकतें महिलाओं पर हो रही हिंसा के लिए कभी चाउपीन तक नहीं पहुँच सकती। इसके बावजूद यह कभी नहीं हो सकता कि दक्षिणांशी ताकतें महिलाओं पर हो रही हिंसा के लिए कभी चाउपीन तक पहुँच सकती।

अंग्रेज विदेशी

निहित पुरुषप्रधानता का नतीजा मानने से इंकार कर देते हैं नतीजतन हमारे देश की आधी आबद्धी जिसे हर नेता 3

विवरण का कुछ आवाज़ा न इस फसल का छुट्टेंडू मात्र ठहरा दिया। उनका तर्क है की कंप्रेस ने केवल एक ही राज्य में यह घोषणा क्यों की इस फैसले के विरोधी राजनीति में प्रतीकात्मकता की अहमियत को कम आंक रहे हैं। यदि कंप्रेस अन्य राज्यों में यह प्रयोग ना भी कर पाए तब भी इस फैसले का महत्व कम नहीं होता। सामाजिक बदलाव रातोरात होने वाली चीज़ नहीं है बल्कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इस फैसले को एक सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। इस फैसले ने महिलाओं के स्वाल को भारत की पुरुषप्रधान राजनीति में कुछ देर के लिए ही सही लेकिन केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। वर्तमान राजनीतिक रिमर्श में महिलाओं के मुद्दे मात्र उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सीमित रह गए हैं। महिलाओं का मुद्दा कानून - व्यवस्था दुरुस्त करने का मुद्दा बनकर रह गया है। आलम यह है की दक्षिणांची ताकतें महिलाओं पर हो रही हिंसा के लिए कभी चाउमीन तो कभी मोबाइल फोन को दोषी ठहराते हैं। वह इसे सामाजिक संरचना में नताजतन हमार देश का आधा आबादा। जिस हर नता अपने भाषण में तालियों के लिए देवी का रूप बतलाता है, कैसे रोज़मर्रा का जीव जीती है और किन चुनौतियों का सामना करती है उससे समाज अभी तक अनभिज्ञ है। यौन हिंसा के अलावा महिलाएं हर क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करती हैं, चाहे वह शिक्षा हो या ऑफिस या घर में कर रहा श्रम को अनदेखा किया जाना हो या फिर अपने काम का पूरा दाम न पाना हो, हर कदम पर उन्हें भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस दिन महिलाएं अपने श्रम के हिसाब मांग लेंगी उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ जाएगी। प्रियंका गांधी का फैसला महिलाओं के प्रति इस समग्र दृष्टिकोण से जन्मा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी राजनीतिक दल या नेता ने महिलाओं के लिए कोई कदम नहीं उठाए। लेकिन यह पहल केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित थी। चाहे वह कन्यादान योजना हो या शराब बंदी हो या लड़कियों को मुफ्त साइकिल वितरण की योजना हो

महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट देने की घोषणा एक सकारात्मक पहल

भारत का आमने-हस्सा ह, जमू-कश्मीर में हर भारतवासी पूरा तरह सुरक्षित रहेगा चाहे हिन्दु हो या सिख, बिहारी हो या पंजाबी अथवा बंगाली। जमू-कश्मीर राज्य में पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां बेअसर होती रही हैं। अब उसने नयी रणनीति उन गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने की बनाई जो इस राज्य के विकास और इसकी अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। कश्मीर में विकास की जो गंगा प्रवाहमान हुई है, वह अनवरत गतिमान रहेगी। सच्चाई है कि पिछले दो साल में इस राज्य में नागरिकों के विकास की कई केन्द्रीय परियोजनाएं चालू की गई हैं और उनके अच्छे परिणाम भी आने शुरू हुए हैं। पर्यटन गतिविधियां तेज हो रही हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से इस का आवश्यकता व्यक्त का, जिनके कारण आताकथा आर उनक समर्थकों ने किर से सिर उठाने का दुस्साहस किया। कश्मीर में जितनी जरूरत आतंकियों पर दबाव बनाने और उन्हें बचकर निकलने के अवसर न देने की है, उतनी ही उनके समर्थकों पर शिकंजा कसने की है। आतंकियों के समर्थक केवल वे ही नहीं हैं, जो उन्हें शरण, सहायता एवं संरक्षण देते हैं, बल्कि वे भी हैं जो उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं, जिनमें राजनेता, नौकरशाह एवं सरकारी कर्मचारी भी हैं। जो घर का भेदी लंका ढाहवे वाली स्थिति वाले होते हैं, इन खतरनाक एवं राष्ट्र-विरोधी तत्वों से कैसे निपटा जाये, यही इस सुरक्षा समीक्षा का मुख्य हार्द है, गहनता एवं समग्रता है। शाह की यह तीन दिन की यात्रा न केवल कश्मीर के लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से आश्वस्त करने का सक्षम वातावरण निर्मित करेगी बल्कि कश्मीर में राष्ट्रीयता को भी मजबूत बनायेगी। इसके लिये शाह को सबसे पहले यही श्रेय जाता



खूब सुरंत राज्य का सर करने लगा भारा तादाद में आने लग है। कश्मीरी जिस गर्मजोशी के साथ अपने भारतीय नागरिकों के स्वागत करते हैं और उनकी मेजबानी करते हुए अपनी सहृदयता आत्मीयता और ईमानदारी की छाप छोड़ते हैं उससे पूरे भारत में जम्हू-कश्मीर की छवि में चार चांद लग रहे हैं और दूसरे राज्यों वे लोगों से कश्मीरियों की आत्मीयता एवं सौहार्द बढ़ रहा है। आप कश्मीरी जनता एक नया संतोष महसूस कर रही है। यह स्थिति कई दृष्टियों से अनूठी है, प्रेरक है। आजादी के अमृत महोत्त्व का मनाते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र कश्मीर के साथ अंतरंगता एवं एकात्मता महसूस करने लगा है, इन सुखद स्थितियों को खंडित करने के पाकिस्तान की नयी रणनीति को असफल बनाने में भारतीय सेना के जवान अनुठे उपक्रम करते हुए आतंकियों को चुन-चुन कर मारने का जो अभियान पिछले दस दिनों से चला रही है उससे राष्ट्रविरोधी तत्वों के हौसले पस्त होने जाहिर हैं। शाह ने इसके लिये न केवल सेना के अधिकारियों एवं जवानों को अधिक सतर्कता एवं सावधानी से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये जागरूक किया बल्कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के लिये भी चेताया है। शाह ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का काम न केवल समग्रता से किया है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को अधिक दुर्स्त एवं चौकस बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सुरक्षा की गंभीर समीक्षा करते हुए उन कारणों को पहचान कर उनका निवारण किये जाना

का आवायकता व्यक्त का, जिनक कारण आताकथा आर उनक समर्थकों ने फिर से सिर उठाने का दुस्साहस किया। कश्मीर में जितनी जरूरत आतंकियों पर दबाव बनाने और उहें बचकर निकलने के अवसर न देने की है, उतनी ही उनके समर्थकों पर शिकंजा कसने की है। आतंकियों के समर्थक केवल वे ही नहीं हैं, जो उन्हें शरण, सहायता एवं संरक्षण देते हैं, बल्कि वे भी हैं जो उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं, जिनमें राजनेता, नौकरशाह एवं सरकारी कर्मचारी भी हैं। जो घर का भेदी लंका ढाहवे वाली स्थिति वाले होते हैं, इन खतरनाक एवं राष्ट्र-विरोधी तत्वों से कैसे निपटा जाये, यही इस सुरक्षा समीक्षा का मुख्य हार्द है, गहनता एवं समग्रता है। शाह की यह तीन दिन की यात्रा न केवल कश्मीर के लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से आश्वस्त करने का सक्षम वातावरण निर्मित करेगी बल्कि कश्मीर में राष्ट्रीयता को भी मजबूत बनायेगी। इसके लिये शाह को सबस पहले यही श्रेय जाता है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर पूरी तरीके से संविधान लागू करके इसे भारत में समावेशी रूप में अन्तर्रंगता प्रदान की। क्योंकि आम कश्मीरी प्रारम्भ से ही भारतीयता के रंग में रंगा रहा है और उसने पाकिस्तान की मजहबी संकीर्ण मानसिकता एवं स्थानीय स्वार्थी राजनेताओं को कभी तवज्जो नहीं दी। यह भी ऐतिहासिक सच है कि 1947 में जब भारत को बांट कर पाकिस्तान बनाया जा रहा था तो कश्मीर की आम जनता इसके खिलाफ थी। इसकी खास वजह यही थी कि कश्मीरी संस्कृति किसी भी ज़ेहादी या कट्टुरपंथी विचारधारा का विरोध करती रही है। यही कारण है कि शाह के 370 समाप्त करने के फैसले का राज्य की जनता ने विरोध नहीं किया। भले आतंकवादी एवं अलगाववादी मानसिकता से जुड़े तथाकथित राजनेताओं | को यह निणच्य खटका।

शाह ने अपनी इस यात्रा में कश्मीर की जनता के दिलों में शांति, अमन एवं विकास की राष्ट्रीय धारा को बलशाली बनाया है। अपनी यात्रा के पहले दिन ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पैक्टर परवेज अहमद डार के निवास पर जाकर विनम्रता एवं आत्मीयता से पीड़ित परिवार के लोगों से भेंट की और शहीद की पतनी को सरकारी नौकरी दी। यह संकेत इस बात का है कि राष्ट्र के अस्तित्व एवं अस्मिता की सुरक्षा पर जान लुटाने वाले हर कश्मीरी का ध्यान सरकार रखेगी। इसके साथ ही उन्होंने श्रीनगर से शारजाह की हवाई यात्रा खोलने का भी ऐलान किया जिससे पूरी दुनिया को लगे कि कश्मीर नये माहौल, राष्ट्र की मूल धारा में पूरी तरह ढल चुका है और इसके लोग सामान्य भारतीयों की तरह ही मुल्क द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। कश्मीरियों में इस विश्वास एवं आशा के प्रस्फुटित एवं पल्लवित होते अंकुर बताते हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि हर कश्मीरी भारत का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, भारतीयता ही उसकी आत्मा है, संस्कृति है। शाह की यात्रा पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देने का एक प्रभावी उपक्रम है कि वह हिन्दू-मुसलमान या मजहब को आगे लाकर कश्मीरियों के उस विश्वास को नहीं डिगा सकता जो उनका भारत में है।

यूपी चुनाव के  
लिए कमज़ोर  
हैं विपक्षी दल

रविश अहमद

चुनावी बिसात के साथ मैदान में लगभग उत्तर चुके राजनीतिक दलों के सामने भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना खासा चुनौतीपूर्ण सवित हो रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव की डागर इतनी आसान नहीं जितनी विपक्षी राजनीतिक दल आस लगाकर बैठे हुए हैं यहां भाजपा से पार पाकर सत्ता में आना किसी भी दृष्टिकोण से आसान नहीं है। दरअसल भाजपा को सत्ता से अलग करना किसी भी राजनीतिक दल के बस में नहीं है। जहां एक और विपक्षी राजनीतिक दल किसानों की नाराज़ी का फायदा उठाने के लिए किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती मंहगाई और रोज़गार जैसे मुद्दों पर सरकार से नाराज़ लोगों वोट अपने पक्ष में मिलाना मानकर चल रहे हैं इसके अलावा सभी की नज़र भाजपा के खिलाफ़ पड़ने वाले करीब 22 प्रतिशत मुस्लिम वोटर पर टिकी हुई हैं और सभी की चाहत यही है कि यह मत प्रतिशत पूरा पूरा उनके खाते में आ जाए तो बाकी थोड़ा थोड़ा मत प्रतिशत मिलाकर भाजपा का गत चुनाव में हासिल किया गए कुल मत प्रतिशत का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। यह वो तमाम बिंदु हैं जिन्हें विपक्षी दल मानकर चल रहे हैं जबकि इसके विपरित यदि ग्राउंड ज़ीरो पर आंकलन किया जाए तो भाजपा अधिक सशक्त होती नज़र आ रही है।

सबसे ज्यादा मज़बूती के साथ जनता के बीच अगर कोई कार्य करता दिख रहा है तो वह सिफ़ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें बृथ लेवल कार्यकर्ता से भी नीचे के स्तर पर गोटर लिस्ट के पेज कार्यकर्ता तक मेहनत की जा रही है वहीं दूसरी ओर अगर सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के विषय में एक एक लाइन में लिखा जाए तो समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में बन रही लहर की आस में जंग के मैदान के किनारे बैठकर चुनाव के इंतजार में है, कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को भुनाना चाहती है इसलिए किसानों के आकर्षण का केंद्र बनना चाहती है यह अलग बात है कि ज़मीन पर कांग्रेस की मेहनत सपा से थोड़ी ज़्यादा है। बहुजन समाज पार्टी केवल ट्रीट के माध्यम से चुनावी बिसात बिछाए हुए हैं जबकि क्षेत्र में उसके कार्यकर्ता हथियार डाले सिपाही से नज़र आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल जाट बाहुल्य क्षेत्रों के सहारे अपने समीकरण फिट मानकर चल रही हैं। आजाद समाज पार्टी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लेकिन वास्तविकता केवल यही है कि वह सिफ़ बहुजन समाज पार्टी के गोट बांटने में सफल होती दिख रही है। बांकों बचे दलों का भी लगभग यही हाल है। इसलिए यह कहने में कोई परेशानी नहीं है कि भाजपा को हरा पाना सभी विपक्षी दलों के लिए एकजुट होकर मेहनत किए बिना दूर की कौड़ी साबित होना तय है। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव तक क्या समीकरण बने और जनता का रझान किस ओर पलट जाए या फिर बरकरार रहे यह भविष्य के गर्भ मेंछिए हैं लेकिन अभी तक कार्यकर्ताओं की मजबूती के मामले में कोई भी विपक्षी राजनीतिक दल भाजपा से टक्कर लेता नज़र नहीं आ रहा।



